पुनरीक्षण अपराधी।
माननीय न्यायमूर्ति *एस. सी. मित्तल* के समक्ष
लेहरी और अन्य, - *याचिकाकर्ता।*
बनाम
अमर सिंह और अन्य, *उत्तरदाता।*
1970 का सी.आर. 448
24 अप्रैल, 1974।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (1958 का XX) - धारा 4 *और* 6 - *न्यायालय ने धारा* 4 *के तहत अपराधी को कारावास की सजा नहीं देने का विकल्प चुना - परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगना - क्या अनिवार्य है।*

और रूप अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 और 6 के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय, धारा 6 की उप-धारा (1) न्यायालय को उसे कारावास की सजा देने से रोकती है जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि धारा 3 या 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा। यदि न्यायालय ऐसे अपराधी को कारावास की कोई सजा देता है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। यदि न्यायालय का विचार है कि धारा 3 या 4 के तहत अपराधी से निपटना वांछनीय नहीं होगा, तो उसे परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगना और उस पर विचार करना आवश्यक है। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट बुलाना केवल तभी अनिवार्य है जब न्यायालय को लगता है कि अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत अपराधी से निपटना वांछनीय नहीं होगा। जब न्यायालय अपराधी को कारावास की सजा नहीं देने का विकल्प चुनता है, तो परिवीक्षा अधिकारी से कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 4 (2) कहीं भी न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगने का अधिकार नहीं देती है और यह केवल यह निर्धारित करती है कि यदि रिपोर्ट है, तो न्यायालय इसे ध्यान में रखेगा। जब धारा 6 में रिपोर्ट के बिना एक अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने की आवश्यकता होती है, तो यह निर्धारित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं लगता है कि इस तरह की रिहाई का आदेश नहीं दिया जा सकता है। 1) में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का अभाव। इसलिए, यदि न्यायालय अपराधी को कारावास की सजा नहीं देने का विकल्प चुनता है तो अधिनियम की धारा 4 (2) के तहत परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए अदालत पर विचार करना अनिवार्य नहीं है।

सीआरपीसी की धारा 430 के तहत याचिका दायर की गई है। *प्रतिवादियों को दोषी ठहराने और रोहतक के अतिरिक्त* सत्र *न्यायाधीश (तृतीय) श्री वीडी अग्रवाल के* 11 नवंबर, 1969 *के आदेश में संशोधन करने के लिए रोहतक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आरएल गर्ग* के 11 नवंबर, 1969 के आदेश में प्रतिवादियों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, *1958 की धारा* 4 *के* तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए रिहा करने की पुष्टि की गई है।

आरोप: भारतीय दंड संहिता की धारा 325/149 *, 323/149 और 148 के तहत।*

आदेश: प्रतिवादियों में से प्रत्येक को 10,000/- रुपये की राशि का बांड निष्पादित करने का आदेश दिया गया था। 2,000 रुपये की राशि के *साथ दो वर्ष की अवधि के लिए इतनी ही राशि की एक जमानत राशि के साथ यह वचन दिया जाएगा कि प्रत्येक को जब भी बुलाया जाएगा, वह उपस्थित होगा और सजा प्राप्त करेगा।*

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता बीएस गुप्ता।*

यू.डी. गौड़, अधिवक्ता, - *उत्तरदाताओं के लिए।* निर्णय

ट्रायल मजिस्ट्रेट के आदेश में नामित प्रतिवादी अमर सिंह और छह अन्य को धारा 325/149 के तहत दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323/149 और 148 के तहत मजिस्ट्रेट ने उन्हें कारावास की सजा देने के बजाय, अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन्हें अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। लहरी और तीन अन्य घायल व्यक्तियों ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। उन्होंने अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत प्रतिवादियों को परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए इस न्यायालय का रुख किया है।

घायल व्यक्तियों के वकील - याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि मजिस्ट्रेट ने परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगे बिना, विवादित आदेश पारित करने में अवैध रूप से कार्य किया। सेकण्ड-

धारा 6 और धारा 4 का प्रासंगिक हिस्सा । 4 निम्नानुसार हैं :-

(1) जब किसी व्यक्ति को ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जिस न्यायालय द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, फिर, इस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, न्यायालय उसे तुरंत किसी भी सजा के लिए सजा देने के बजाय, यह निर्देश दे सकता है कि उसे जमानत के साथ या बिना बॉन्ड में प्रवेश करने पर रिहा किया जाए।	*धारा* 6. (1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कारावास (लेकिन आजीवन कारावास के साथ नहीं) के साथ दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो वह न्यायालय जिसके द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसे कारावास की सजा नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि, अपराध की प्रकृति सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और अपराधी के चरित्र के कारण, धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होना चाहिए, और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास की कोई सजा देता है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा।

(2) उपधारा (1) के तहत कोई आदेश देने से पहले, न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(2) स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि क्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध के साथ धारा 3 या धारा 4 के तहत निपटना वांछनीय नहीं होना चाहिए, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट, यदि कोई हो, और अपराधी के चरित्र और शारीरिक और मानसिक स्थिति से संबंधित उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा।

दो खंडों से पता चलता है कि

21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, कानून न्यायालय को उसे कारावास की सजा देने से रोकता है जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि धारा 3 या 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा और यदि न्यायालय अपराधियों पर कारावास की कोई सजा पारित करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करेगा। धारा 6 की उप-धारा (2) में आगे प्रावधान है कि यदि न्यायालय का विचार है कि धारा 3 या 4 के तहत अपराधी से निपटना वांछनीय नहीं होगा, तो वह परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगेगा और उस पर विचार करेगा। धारा 6 की योजना में, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को बुलाना केवल तभी अनिवार्य है जब न्यायालय को लगता है कि अधिनियम की उपर्युक्त दो धाराओं के तहत अपराधी से निपटना वांछनीय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यदि अदालत, जैसा कि धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक है, अपराधी को कारावास की सजा नहीं देने का विकल्प चुनता है, तो परिवीक्षा अधिकारी से कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, यह देखा जाएगा कि इसकी उप-धारा (2) को धारा 6 की उप-धारा (2) के समान शर्तों में तैयार नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि पूर्व धारा कहीं भी न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मांगने का आदेश नहीं देती है और यह केवल यह निर्धारित करती है कि यदि यह है तो न्यायालय इसे ध्यान में रखेगा। मामले का एक अन्य पहलू यह है कि धारा 4 का लाभ उन व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है। चूंकि धारा 6 में रिपोर्ट के बिना अपराधी को परिवीक्षा पर रिहा करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं लगता है कि रिपोर्ट के अभाव में धारा 4 (1) के तहत, इस तरह की रिहाई का आदेश नहीं दिया जाएगा। मैं हरभजन सिंह बनाम हरभजन सिंह मामले में सी जी सूरी और जे द्वारा अपनाए गए इसी तरह के दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं । *तरलोक सिंह और अन्य,* 1972 का आपराधिक संशोधन संख्या 54-आर (1)। मैं आगे राय रखता हूं कि धारा 4 (1) अदालत को मामले की परिस्थितियों का संबंध रखने का निर्देश देती है, जिसमें अपराध की प्रकृति और अपराधी **का** चरित्र शामिल है। अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियां आम तौर पर अदालत के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। जहां तक अपराधी के चरित्र का संबंध है, वर्तमान मामले की तरह आहत मामलों में, घायल पक्ष अपराधी के बुरे पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, को न्यायालय के ध्यान में ला सकता है, मामले के इस दृष्टिकोण में, जब किसी मामले के रिकॉर्ड पर सामग्री न्यायालय को संतुष्ट करती है कि अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अपराधी को रिहा करना समीचीन है, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत सम्मान के साथ, मैं *राज्य बनाम नकेश* जी. शेट गोवनकर और अन्य *मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा* व्यक्त किए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हूं, (2) कि धारा 4 (2) के संदर्भ में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को मंगाना और उस पर विचार करना न्यायालय के लिए अनिवार्य है और यह धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत पारित आदेश की वैधता या वैधता के लिए एक शर्त है।

अब यह देखने की आवश्यकता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित परिवीक्षा पर प्रतिवादियों की रिहाई वैध है या नहीं। वर्तमान मामले की परिस्थितियां यह हैं कि सात प्रतिवादी और शिकायतकर्ता-पक्ष के चार सदस्य (इस न्यायालय में याचिकाकर्ता) रोहतक शहर में पड़ोसी हैं। घटना के दिन याचिकाकर्ता अपने घर के सामने चारपाई पर बैठकर *हुक्का* पी रहे थे। प्रतिवादियों के परिवार से संबंधित श्रीमती कार्को ने घर लौटते समय याचिकाकर्ताओं द्वारा मार्ग पर बाधा डालने पर आपत्ति जताई। यहां तक कि जब याचिकाकर्ता चारपाई हटाने के लिए सहमत हो गए, तब भी वह उन्हें गाली देने से बाज नहीं आईं। इस बीच, तलवार, भाले और *लाठियों* से लैस सात उत्तरदाता आए, हमला किया और उन्हें गंभीर और साधारण चोटें आईं। यह स्पष्ट है कि पार्टियां अतीत में अच्छे पड़ोसियों के रूप में रह रही थीं। दूसरे शब्दों में, उनके बीच किसी भी दुश्मनी का अस्तित्व किसी का मामला नहीं है। जैसा कि मजिस्ट्रेट ने कहा, यह घटना अचानक हुई थी और श्रीमती कार्को और याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद के परिणामस्वरूप हुई थी। उत्तरदाताओं में से किसी के चरित्र के खिलाफ, रिकॉर्ड पर या संशोधन के आधार पर कोई कलंक नहीं है। जैसा कि एक्स रतन लाल बनाम सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने कहा था। *पंजाब राज्य* (3), "अधिनियमपेनोलॉजी के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति के विस्तार में एक मील का पत्थर है।

(1) सीआर आर 54-आर/72 पर 19.9.73 को निर्णय लिया गया:

(2) ए.आई.आर. 1970 गोवा, दमन और दिन 49.
(3) ए.आई.आर. 1965 एस.सी.: 444:

चानन मल *बनाम* हरियाणा राज्य, आदि (बी. आर. तुली, जे.)

यह सिद्धांत की मान्यता का परिणाम है कि आपराधिक कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत अपराधी को दंडित करने की तुलना में सुधार करना अधिक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषामें इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा